[Shri I. K. Gujral]

we have come to definite conclusions that it is not possible for us to function as it is, on the basis of honorary members only. That is why all the amendments. But what Mr. Hazra's amendment suggests will defeat the scheme itself. Therefre, I regret I cannot accept it.

Shri R. R. Sharma's amendment also is similar to the one of Shri Hazra. We have experimented over a number of years on the basis of honorary members and we have not succeeded. That is why we have set up the Khosla Committee on the basis of whose recommendations we are amending this law. We want to introduce an element of whole-time members. My friend Mr. Daga was very much worried about one thing: Why this legal quibble as to whether assessors should be paid or not paid? It is made clear that assessors are not going to be whole-time members; assessors are going to be there whenever they are called to assess a film; they will get allowance. That is the main spirit behind the Bill.

SHRI R. R. SHARMA: He is confused with the word 'salary' and 'allowances'.

SHRI I. K. GUJRAL: Mr. Daga has a legal mind.

SHRI M. C. DAGA: You have given the provision that the assessors will be appointed by the Board. They will not get salary. Why do you put the words, receive such fees and allowances as may be prescribed? What is the necessity for this? You say already, *fees and allowances, as prescribed in the rules.*

SHRI I. K GUJRAL: I have already said about this. This is merely legal quibble.

MR. CHAIRMAN: I will now put Amendment No. 5 of Shri Sharma to the vote of the House.

Amendment No. 5 was put and negatived

MR. CHAIRMAN: I will now put amendments Nos. 9 and 10 by Shri Daga to the vote.

AN HON. MEMBER: He wanted to withdraw.

SHRI M. C. DAGA: I want leave to withdraw.

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: No, Sir.

MR. CHAIRMAN: All right, I will put the amendments to vote.

Amendments No. 9 and 10 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: I will now put amendments Nos. 20, 21 and 22 to the vote of the House.

Amendments Nos. 20, 21 and 22 were put and engatived.

MR. CHAIRMAN: So, the amendments are negatived.

The question is:

"That Clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now we take up the next item on the Agenda-half-an hour Discussion.

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

CRITERIA FOR ALLOTMENT AND QUANTITY OF FOODGRAINS ALLOTTED TO STATES DURING JANUARY TO JUNE 1974

MR. CHAIRMAN: Now we may take up half-an-hour discussion, Shri Ramavtar Shastri.

[DR. HENRY AUSTIN *in the Chair*].

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, यह आधे घंटे की चर्चा में अपने 22 जुलाई को पूछे गए प्रश्न सं० 9 के संबंध में उत्पन्न सवालों पर उठा रहा हूं ।

सभापति जी, 26-27 वर्षों की आजादी के बावजूद हमारा देश आज भी भीषण अन्न संकट में फंसा हुआ है । सम्पूर्ण देश की 55 या 56 करोड़ जनता भीषण महंगाई, अभाव और मूल्यों में वृद्धि से तंग और तबाह हो रही है । हमने उम्मीद की थी कि आजादी के बाद के मामलों में हमारा देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो जायगा, लेकिन यह आशा पूरी नहीं हुई, जिस की सारी जवाबदेही यहां की सरकार के ऊपर है । आज हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि आज इस राज्य में भुखमरी से लोग मर रहे हैं तो कल उस राज्य में मर रहे हैं । आज सवेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करते समय आसाम में भुखमरी से मृत्यु की बात उठाई गई थी, मध्य प्रदेश में भूख से मौतें हुई हैं, सूबा बिहार में तो अकसर लोग भूख मरते रहते हैं कभी राजस्थान कभी उड़ीसा की बात आती है—कहने का मतलब यह है कि देश के विभिन्न भागों में भुखमरी की स्थिति कायम है और सरकार अपनी किसान विरोधी नीति की वजह से गल्ला, चोरों मुनाफाखोरों की मदद करने की वजह से, गल्ले की समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रही है, कीमतों को बांधने में नाकामयाब रही है और जनता तक अनाज पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने में असफल रही है ।

सभापति जी, राज्यों को सरकारी खजाने से जो गल्ला दिया जाता है उस का सिद्धांत या मापदण्ड सही नहीं है, मनमाने तरीके से गल्ले का बटवारा सरकार करती है । इस में राजनीति भी खेली जाती है । जिस को चाहा उसे दे दिया । वास्तव में कमी के राज्यों को आवश्यकता के मुताबिक या इन के जारा आंबटन के मुताबिक गल्ला नहीं दिया जाता इस का प्रमाण—हमारे प्रश्न के उत्तर में जो आंकड़े पेश किए गए हैं—उन से स्पष्ट है । इन्होंने उन राज्यों को भी आवंटन किया, जहां जरूरत के मुताबिक गल्ला पैदा होता है या उस से ज्यादा पैदा होता है या उन राज्यों को दिया गया जहां गल्ले की कमी है या पूरा पैदा नहीं होता है । कमी वाले राज्यों के साथ इन्होंने मुंह देखा काम किया है, पूरा गल्ला नहीं दिया । मैं यह नहीं कहता कि आप ने बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन जो मात्रा आप आवंटित करते हैं उस को देने की कोशिश करनी चाहिए । इस वक्तव्य में 30 राज्यों की गिनती की गई है, जिसमें हिन्दुस्तान के सभी राज्य शामिल हैं । पंजाब भी शामिल है, हरियाणा भी शामिल है, जहां गल्ले की उपज अधिक होती है । इस में बिहार, गुजरात, उड़ीसा, आसाम, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल जहां कम गल्ला पैदा होता है—ऐसे राज्यों के नाम भी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि आप की गल्ला आवंटन करने की नीति क्या है तथा आपको उसे ठीक तरह से निर्धारित करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं—आप ने बिहार को जनवरी से जून तक 210 हजार टन गल्ला देने का तय किया था लेकिन आप ने दिया 179 हजार टन । ऐसे और भी कई राज्य हैं जिन्हें निर्धारित कुछ दिया लेकिन किसी को अधिक दे दिया और किसी को कम दिया। इसी अर्थ में मैंने कहा है कि आप के सिद्धांत या मापदण्ड मनमौजी हैं, अपनी मर्जी की बात है, जो सरकार के दिल में आया, मंत्री महोदय के दिमाग में आया, वैसा आवंटन कर दिया । मैं चाहूंगा कि आवंटन के सिद्धान्त को निरूपित कीजिए और उस के अनुसार ही दीजिए । आप कहते हैं कि हमारे स्टाक में जितना गल्ला होता है और जहां कमी होती है उस को देख कर तथा कुछ अन्य बातों को देख कर हम गल्ला आवंटित करते है । ये अन्य बातें क्या हैं-- कृपा करके बतलाइये ?

मेरे प्रश्न के तीसरे हिस्से में मैंने बिहार के बारे में पूछा था—बिहार की स्थिति बहुत संकटमय है । आप जानते हैं वहां जनता में असन्तोष है, लोग भुखमरी के कगार पर खड़े है, उन को पर्याप्त गल्ला नही दिया जाता, यह डेफिसिट राज्य है, जरूरत से कम गल्ला पैदा करता है । इस लिये लोगों को गल्ला नही मिल रहा है—न आप की राशनिंग की दुकानों से मिलता है और न बाजार में मिलता है । लोग बहुत परेशान हैं—पटना शहर में ही 60 प्रतिशत लोग ऐसे है जो दोनों वक्त खाना नही खाते, या तो उन के अन्दर खरीदने की शक्ति नही है या उन को मिल नही पा रहा है—इस लिये उन को कठिनाई है । चावल चार रुपया किलो बिक रहा है ।

सभापति महोदय 1971 की मर्दम-शुमारी के मुताबिक बिहार की जनसंख्या 5 63 53 369 थी, 1 अप्रैल, 1974 को यह जनसंख्या 6,01.55 117 हो गई । इन तमाम लोगों के खाने के लिये गल्ले की आवश्यकता है—93.36 700 मीट्रिक टन । इस के अलावा बीज के लिये, कुछ जानवरों का भी हमारे यहां गल्ला खिलाते है, उस के लिये 9,33 670 मीट्रिक टन की जरूरत है दोनों को मिला कर 1 02 70,370 मीट्रिक टन गल्ले की जरूरत है । बिहार पैदा करता करता है—1973–74 में बिहार में 85 69,000 मीट्रिक टन पैदा हुआ, अब शेष रह जाता है 17 लाख मीट्रिक टन का । जाहिर है ऐसी परिस्थिति में वहां भुखमरी की समस्या उत्पन्न होगी, इस 17 लाख टन की कमी को पूरा करने के लिये आप देते हैं—केवल 35 हजार टन । आप ने 40 हजार टन देने का वायदा किया था, लेकिन मोटा-मोटी 35 हजार टन जनवरी से जून तक दिया । 5 हजार टन बाजार देने की बात थी लेकिन आप ने बाजार तो बिल्कुल ही नही दिया । जाहिर है इस से उन की दिक्कत बढ़ेगी ।

इस के अलावा सरकार ने 50 हजार टन गल्ला खरीदने के लिये व्यापारियों को परमिट दिये, 50 हजार टन राज्य सरकार स्वयं हरियाणा और पंजाब से लाना चाहती है, लेकिन 6500 टन ही खरीदा गया । नेपाल से 10 हजार टन चावल लायेंगे, पहले नेपाल से 1 लाख टन चावल खरीदते थे लेकिन अब गुजरात या दूसरे राज्य नेपाल को अधिक दाम देकर खरीदते हैं जिस से सारा चावल उधर चला जाता है, इस लिये अब बिहार को नेपाल से केवल 10 हजार टन की ही आशा है । इस तरह से कुल मिला कर बिहार को 7 लाख 40 हजार टन गल्ले की प्राप्ति होगी, यदि 17 लाख टन की कमी में इस को काट दिया जाय तो भी 10 लाख टन की कमी बिहार में रह जाती है । ऐसी हालत में वायदा कर के भी यदि आप नही देंगे तो वहां क्या स्थिति उत्पन्न होगी आप स्वयं समझ सकते है । बिहार के लिये अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर के महीने ज्यादा संकट के महीने होंगे । हर महीने 1 लाख टन गल्ला अगर आप नही देंगे तो उसे संकट से बचा नही सकेंगे और जो लोग इस संकट से फायदा उठा कर देश में फासिटावाद की स्थापना करना चाहते हैं, उन के लिये आसानी होगी इस लिए इन तीन महीनों में ज्यादा दीजिये । इसके अलावा 10 लाख टन की आपूर्ती आपको अपने स्टाक से करनी चाहिये क्योंकि आप को औद्योगिक मजदूरों को भी देना पड़ता है । इसके अलावा बिहार में बाढ़ आती है, सूखा पड़ता रहता है । उसके लिए कम से कम पचास हजार टन अतिरिक्त गल्ले की जरूरत है । अगर तमाम बातों पर विचार किया जाए तो दस लाख टन की तो कमी है ही जिस की पूर्ति होनी चाहिये ।

आपने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वे गल्ला चोरों पर हमला करें, छिपे गल्ले को वहां से निकालें । इस आदेश का कहां तक पालन हो रहा है ? बिहार की

बात मैं जानता हूं । मिनिस्टर लोग जो पकड़े जाते हैं उनको छुड़वा देते हैं और हजार मन गल्ला जो निकला है उसको भी छोड़ दिया जाता है । और जगह भी इस तरह की बात होती होगी । अगर ऐसा हुआ तो काम चलने वाला नहीं है ।

बिहार की आज की राजनीतिक स्थिति को आप देखें । वहां संकट की स्थिति है । वहां जो गल्ले की आज कमी है उसको आप देखें । मुनाफाखोरों पर, गल्ला चोरों पर आप तेजी से हमलें करने के लिए, उन से छिपे गल्ले तथा दूसरे सामान को निकालने के लिए आदेश दें, कड़ाई के साथ इन आदेशों का पालन हो और जो पकड़े जाएं उनके ऊपर कड़ाई बरतें । यह होता नही है, इस वास्ते इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिये ।

रेल मंत्री ने कहा है कि रेल मजदूरों को सस्ती गल्ले की दूकानों से गल्ला दिलाने की वह व्यवस्था करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि आपकी उनके साथ क्या कोई बातचीत हुई है और अगर हुई है तो उसका ब्यौरा क्या है। जिन सवालों को मैं पूछना चाहता हूं उनकों में पढ़ देता हूं :

मैं पूछ चुका हू कि सरकार ने खाद्यान्न के आबंटन का कौन सा सिद्धान्त, कौन सा मानदण्ड तय किया है ? देश में खाद्यान्न की कुल उपज कितनी है तथा आवश्यकता कितनी है और कितनी कमी खाद्यान्नों की रह जाती है? क्या आपने खाद्यान्नों के अभाव को देखते हुए खाद्यान्नों के आयात का निर्णय कर लिया है,यदि हां तो कितने खाद्यान्नों का तथा भिन्न-भिन्न देशों से और कितना धन आप इस पर खर्च करने जा रहे हैं ? खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार ने कौन सा कार्यक्रम निर्धारित किया है तथा उसकी कार्यान्विति की क्या स्थिति है? बिहार सरकार ने खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए क्या आपके पास कोई ज्ञापन या मैमोरेंडम भेजा है यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की उसके बारे में प्रतिक्रिया क्या है? राज्य सरकारों को छिपे गल्ले तथा अन्य आवश्यक सामग्री को निकाल बाहर करने के लिए छापे मारने के क्या आपने आदेश दिए हैं । यदि हां तो विभिन्न राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कारंवाई का ब्यौरा क्या है? क्या रेल मजदूरों को अनाज सप्लाई करने की कोई व्यवस्था की गई है यदि हां तो कौन सी और यदि नही तो इस सम्बन्ध में आपकी रेल मन्त्री या रेल मन्त्रालय से कोई बात हुई है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है?

मैं चाहता हूं कि इन तमाम बातों में आप सदन को विश्वास में ले और बताएं कि कैसे आप सचमुच मे जनता को भुखमरी, अभाव तथा इस तरह की दूसरी तकलीफों से बचाना चाहते हैं? हमें ठोस प्रमाण मिलना चाहिए, केवल बातें करके अपने आप कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझ लें । हम जानते हैं कि हमारे सूबे में अगले तीन महीने में अगर एक लाख टन प्रति महीने के हिसाब से अनाज का प्रबन्ध नहीं किया गया तो हजारों लोग भूखे मर जाएंगे और आप बयान देते रहेंगे कि कोई नहीं मरा, और लोग मरते रहेंगे । इस वास्ते मैं आप से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि मुनाफाखोरों और गल्ला चोरों के सामने आप

घुटने टेकने की नीति का परित्याग करें। साथ ही खाद्यान्न तथा दूसरी आवश्यक सामग्रियों को राज्य व्यापार के जरिये उपलब्ध करा करके आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मशीनरी के जरिये बटवारे का इंतजाम करें ताकि लोग मरें नहीं और प्रयाप्त माला में राशन की दुकानों में गल्ला मिल सके।

SHRI B. V. NAIK (Kanara): The hon. Minister has given certain data in reply, and I find that the biggest recipients of food are his home State of Maharashtra, which has got 25 per cent of the total allotment in the country, and then the little State of Delhi from which my hon. friend Shri H. K. L. Bhagat hails. One is very near the seat of bureaucratic power, namely the Government of India, and the other is very near the other seat of political power, namely Mr. Shinde. I would recall that the other day, I had rightly remarked that Shri Ramavatar Shastri should be properly briefed. The other day, when we had raised this question, the hon. Minister did not find time to reply to our question; I would not say that he did not have the courtesy to reply. Even the proceedings have not recorded what we had heard. After all, we take this as an opportunity to urge certain local issues.

I am referring to the summary of the proceedings that is given.

Reverting to the point which has been put forth by the Minister that the allotments are made keeping in view the availability of foodgrains in the central pool and the requirements of the deficit States and other relevant factors, what are the objective considerations? Is it on the basis of quantification of a particular problem or of assessing the need? 'Availability' may mean something. You cannot distribute more than what we have. Then there is reference to 'other relevant factors' in part (a) of the statement. This virtually says nothing. It is vague and it says less than what it conceals.

I would, therefore, like to know from the hon. Minister how the deficit in a particular State is assessed. Do you assess it on the basis of the prices ruling in a particular State? In the State of Tamil Nadu, rice is selling at Rs. 1.50 and in Karnataka it is selling at Rs. 2.50. Is the deficit calculated on the basis of the prices ruling in a particular State of a particular staple dietary commodity? Otherwise, this is going to be an absolutely unfair distribution.

The only other point I would like to urge is this. In September 1973, when there were food riots in our State, it was the MPs who were gharoed. We were the ones who had to face the mob. We know we had absolutely no control over the distribution which is done by the State Government. Since we vote the Demands of the Ministry of Food and Agriculture at the Centre, can we know how these people control the distribution below the State level, because in many of the States wherever there is a defective distribution machinery, the amount of grains coming from the Central pool or whichever pool or local procurement tends to go those influential urban prosperous sections, and the weaker sections of the society, particularly in the rural areas are invariably left to the wolves? I have to say with regret that with regard to distribution in the villages much below the level of the district and other points, the performance of Krishi Bhavan has been absolutely lamentable. Since the people are directly holding us responsible, will the hon. Minister tell us how he is going to control the distribution at the village, the last outpost with regard to foodgrains?

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I shall confine myself to only two questions or two parts of the question. The hon. Minister is aware that in UP, specially the eastern districts of UP, there are certain districts where people really face starvation in spite of the fact that the Chief Minister took a bold and firm stand—I must congra-

tulate him on it—and he was able to unearth some hoarded grain. He might lose his job, but that is a different matter. But the question is, what was the requirement of the UP Government especially for these deficit areas? What did they demand and what total quantity of foodgrains was given by the Central Government in 1973 and till now in 1974? Is he also aware that the Chief Minister made a promise to nearly 50,000 employees who were manufacturing biscuits? In UP in the small scale industrial sector there are units manufacturing biscuits which are almost facing closure because of non-availability of maida which has not been supplied by the UP Government on the ground that they demanded 10,000 metric tonnes as extra quota from the Central Government meant but the Centre has not been kind to them and it has not been given to them I am told that a delegation which came from Kanpur and other places in UP met the hon. Minister Shri Shinde. He was kind and courteous to them. But perhaps again he shifted the ball to the court of the Chief Minister. These people 50,000 people with their family members come to more than 5 to 6 lakhs of people—who depend on biscuit manufacture for their living are facing starvation. Those persons are facing starvation. I should like to know from the hon. Minister what promise was given to the state Chief Minister or Food Minister regarding the supply of foodgrains and whether that promise had been fulfilled and if not, when it is likely to be fulfilled.

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) : सभापति महोदय यह मूल प्रश्न बड़ा गम्भीर था। मुझे आशा थी कि सरकार की ओर से इसका जवाब उसी गम्भीरता से दिया जायेगा लेकिन जवाब पढ़ कर निराशा होती है। मूल प्रश्न में बहुत से मुद्दे उठाये गये हैं किन्तु आवश्यक मुद्दों को छिपा लिया गया है उन पर प्रकाश नहीं डाला गया है और उनका जवाब नहीं दिया गया है।

उदाहरण के लिए :

"availability of foodgrains in the Central pool, requirements of deficit States and other relevant factors."

What are those relevant factors? इसका कोई वर्णन नहीं है। इसी तरह से इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया गया है कि क्या बिहार सरकार ने कुछ मांग की थी।

सरकार स्वीकार करती है कि बिहार की खाद्य स्थिति बहुत दयनीय है और कहती है कि इस बारे में हर आवश्यक कदम उठाया जायेगा। वे कदम क्या हैं इसका भी वर्णन होना चाहिए था।

अगर इन सब बातों का सम्यक रूप में जवाब दिया जाता तो शायद इस हाफ़-आवर डिसकशन की आवश्यकता न होती। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि स्टेट्स को और खास तौर से डेफ़िसिट स्टेट्स को किस आधार पर आवंटन किया जाता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आवंटन के समय आबादी का भी विचार किया जाता है। मुझे प्रतीत होता है कि आबादी का विचार नहीं किया जाता है क्योंकि अगर ऐसा होता तो बिहार की और विशेष कर उत्तर बिहार की यह दुर्दशा न होती। उत्तर बिहार उस राज्य का बहुत थिकली पापुलेटिड पार्ट है। वहां अन्न के लिए हाहाकार मचा हुआ है और बड़ी दयनीय स्थिति है।

जो भी अन्न उपलब्ध है वह शहरी क्षेत्रों में ही दिया जाता है। अगर वह देहाती क्षेत्रों में भी दिया जाये तो बहुत अच्छा हो। क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे ?

जो फ़िगर्ज़ हम लोगों को मिले हैं, उनमें हम देखते हैं कि आबंटन और आपूर्ति में फ़र्क है। मैं यह जानना चाहता हू कि उसका क्या कारण है।

आज अन्न का अभाव है और हम अन्न देकर ही जनता की भूख को मिटा सकते हैं। हम बातों से उसकी भूख को नहीं मिटा सकते है। अगर हम अन्न पैदा नही करेंगे तो हम जनता की भूख को मिटाने में पूर्णतया सक्षम नही हो सकेंगे। इस लिए आवश्यकता है उत्पादन की। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मै मंत्री महोदय से यह उम्मीद करू कि वह देश मे, और बिहार मे, और बिहार में भी खास तौर से उत्तर बिहार में स्टेट ट्यूबवेल्ज़ का जाल बिछाने का प्रयास करेंगे। जिससे सिचाई की सुविधा हो और लोग पर्याप्त अन्न उपजा सकें ?

श्री कमल मिश्र मधुकर (केसरिया). सभापति महोदय मैं कोई भाषण न दे कर केवल यही कहूंगा कि शास्त्री जी ने बिहार का प्रश्न उठा कर बिहार की बडी सेवा की है।

मैं यह जानना चाहता हू कि केन्द्रीय सरकार ने बिहार के प्रति उपेक्षा नीति क्यों अपनाई है। बिहार मिनरल्ज़ के मामले में समूचे देश की आवश्यकता को पूरा करता है। फिर भी अन्न के मामले में बिहार की माग को पूरा नही किया जाता है।

क्या यह सत्य है कि बिहार सरकार सरकारी तौर पर अन्न की ख़रीद मे बिलकुल असफल रही है और केन्द्र ने उसे अन्न की ख़रीद बढाने के लिए कभी परामर्श या निदेश नही दिया है ? उत्तर प्रदेश मे सरकारी ख़रीद के मामले में काफी सफलता मिली है।

क्या यह सत्य है कि बिहार मे इन दो तीन महीनों में अन्न का बहुत अभाव रहा है जिसको देखते हुए केन्द्र यह विचार करने जा रहा है कि अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर में बिहार को स्पेशल क्वोटा दिया जाये ?

बिहार में उपजाऊ भूमि है और सब सुविधायें हैं। अन्न के मामले में बिहार को आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या केन्द्र ने बिहार सरकार के कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों से कोई विचार-विमर्श किया है ?

बिहार सरकार ने एक रिपोर्ट भेजी है, जिस में बताया गया है कि उर्वरकों और बिजली की कमी से उत्पादन में गिरावट हुई है। क्या केन्द्रीय सरकार कोई ऐसे कदम उठा रही है, जिस से बिजली और उर्वरको की आपूर्ति के सिलसिले मे बिहार को सहायता दी जा सके ?

आकडों से प्रकट होता है कि केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन चार सालो मे बिहार को कम अन्न दिया है। 1970 मे 10 लाख टन, 1971 में 8 लाख टन, 1972 मे 9 लाख टन और 1973 में 4 लाख टन अनाज बिहार को दिया गया है। हर साल अनाज की मात्रा में कमी होती जा रही है। क्या वजह है कि बिहार को प्रति-वर्ष अनाज की सप्लाई कम हो रही है जब कि बिहार मे अभाव ज्यों का त्यो बना हुआ है ?

बिहार मे कई बहुत बडी सिंचाई योजनायें पूरी नही हो रही हैं। क्या केन्द्रीय सरकार इस बारे मे बिहार सरकार से विचार-विमर्श करेगी ताकि केन्द्र की सहायता से इन योजनाओं को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाये और बिहार की उपज मे बढोत्तरी हो सके ?

जैसा कि श्री मिश्र ने कहा है क्या केन्द्रीय सरकार बिहार मे अधिक ट्यूबवैल लगाने जा रही है जिस से अन्न की उपज बढ़ाई जा सके ?

बिहार में अन्नोत्पादन के लिए यह बहुत जरूरी है कि भूमि सुधार कानून लागू हों। लेकिन उन्हें लागू नही किया जा रहा है। इस लिए क्या केन्द्रीय सरकार इस बारे में

बिहार सरकार से कोई बचार-विमर्श करने जा रही है ताकि वहां भूमि सुधार लागू किये जाय बड़े जमींदारो की जमीन ले कर छोटे किसानो में बांटी जाये जिससे खेती में तरक्की हो हो सके ?

18 hrs.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI AN' \SAHEB P. SHINDE): Sir, I am thankful to Shastriji for bringing up this discussion because sometimes lack of communication or misunderstanding can create a problem. In the case of Bihar, there seems to be a considerable amount of misunderstanding among members regarding central help to that State. At the outset, I would like to submit that it will be our endeavour and continuous effort to give the maximum assistance to Bihar in regard to the management of its food economy. But in the present political situation in Bihar, some interested parties are trying to exaggerate and add to the difficulties of the management of its food economy at the moment. Perhaps I will not be misunderstood if I say that the food shortage in Bihar is not to acute as is being mentioned, not by hon. member here but by somebody else outside, who are interested in political agitations.

For instance, Shri Shastri made the point that the deficit of Bihar is about 10 lakh tonnes a year. That is to say, if one lakh tonnes of foodgrains are supplied every month, according to him the deficit can be made up. I may say that the actual inflow of foodgrains to Bihar is very close to one lakh tonnes; it is about 75,000 to 80,000 tonnes. When the new wheat policy was adopted, we had to reduce the allocation to all other State Governments because there would naturally be some inflow on trade account in all the deficit States. But we did not reduce the allocation to Bihar. In fact, in the month of August we have increased the allotment to Bihar from 40,000 to 45,000 tonnes. The information which I am giving is the most up to date and the figures which the hon. Members may have will be a little out of date. In addition to that, wheat permits have been issued for 84,000 tonnes to be taken to Bihar and actually 47,000 tonnes have been put on rail. So, by and large, 25,000 to 30,000 tonnes a month would be moved to Bihar on trading account for meeting the requirements of flour mills and other industry. In addition to this, there is no ban on the movement of coarse grains and so quite a large quantity of maize and other things are moving on trade account. So, 70,000 to 80,000 tonnes per month, including Government allotment from the Central pool, are moving to Bihar. Therefore, it should not be very difficult for Bihar to tide over the situation.

I remember that when the United Front Government in Bihar had some political differences with us, they were pressing for the allotment of 4 lakh tonnes a month. Ultimately, the Government of India judiciously came to the conclusion that 1,80,000 tonnes should be enough to meet the requirements, though it was a very difficult situation. Actually, an allotment of that level did help them to meet the situation in 1966-67.

I really feel very sorry for Bihar because ultimately the problem of foodgrains of any State can be solved only by attending to the problems of production and by identifying the factors which are coming in the way of production. North Bihar is very fertile in soil in the whole subcontinent but the yield per acre in North Bihar is the lowest. So, we have to look into the problem. Hon. Members should appreciate that despite difficulties the production of Bihar is coming up. The production in 1970-71 was 78 lakhs which rose to 90 lakh tonnes in 1971-72 and 93 lakh tonnes in 1972-73. The current year's production is quite higher compared to the production

1970-71. So, with the sizable allotment from the Central pool, it should be possible for Bihar to meet the requirements of the situation. I can assure hon. Members that we are constantly in touch with the State Government, we are continuously having dialogue with them and continuously reviewing their position. We shall extend all necessary help to the Bihar Government to tide over the lean months, to which the hon. Member made a reference.

There is some misunderstanding and there is an impression that some arbitrary allotments are made by the Government of India We do not make any arbitrary allotments. There are some very heavy deficit pockets in India like Kerala, West Bengal. Maharashtra, and Gujarat and then comes Bihar Delhi is of course in a different category because it is not a producing area; it is an urban area These are the five problem States from the point of view of food economy. Almost 80 per cent of our food allotment goes to these five States of Maharashtra, Gujarat, Kerala, West Bengal and Bihar, depending on their difficulties. For instance, almost 20 lakh tonnes of foodgrains were given to Bihar in 1967. We do take into consideration the level of production in different areas.

Unfortunately, in this country, the level of per capita consumption differs from State to State In 1965, the Foodgrains Enquiry Committee which went into the problems of food management in the country suggested a food budget and working of a number of details. When we went into details in consultation with the Chief Ministers, we found that this exercise was not likely to lead us anywhere For example, in Haryana, the per head consumption is 220 to 240 Kgs. annually. How can you reduce it? We cannot reduce the per head consumption. If a farmer or a labourer ing 240 Kgs. annually, we cannot reduce his ration. Though rationally, it may appear to be a very sound proposition, in fact, it is a very difficult proposition. In this country, the lowest per capita consumption is in Kerala and the highest is in Haryana Punjab, Himachal Pradesh and J. & K. Therefore, it would be very difficult to think of distributing foodgrains on per head basis, or on the basis of equal quantum. It is a very difficult exercise to do due to different climate conditions, different habits of the people different economic conditions of the people in different States. But the Government of India's effort is that through public distribution system, we are trying to reduce the disparity.

I would like to take this opportunity to dispel an impression as if the Government of India is thinking of reducing public distribution system. I would like to assure the hon Members from Bihar and other States that our intention is to see that public distribution system is not reduced in any way On the contrary we propose to strengthen it Of course, we are having various experiments We learn through experience But our intention is that the level of public distribution system in the country should not be reduced My own understanding of the situation is, whether the present economic difficulties are there or not, that in this country, the public distribution system of a very high size is a must Therefore, it will have to be linked with procurement.

What is necessary is to lay equal emphasis on procurement. Unfortunately, what happens is that we go on making demands With due respect to hon. Members here, there is nothing wrong in that But at the same, we have to lay equal emphasis on procurement also. Unless we procure and substantial quantities come to central pool, how is it possible to make it available to deficit States? We will have to link production procurement and distribution in a very rational way.

[Shri Annasaheb P. Shinde]

Just as we look into the production figures of individual States, at the same time, the consumption pattern in different States is also to be looked into. We have also to take the level of central stocks It is on that basis that we try to make allotments.

Today morning, there was a Question on minimum standard of nutrition which did not come up and which was to be replied by Prof Nurul Hasan. According to the medical standard prescribed, the availability of cereals in this country is almost equal to our requirements. But the difficulty is that we do not get adequate amount of vegetables, adequate amount of fats and proteins in the country. The entire consumption is predominently cereal-oriented We consume too much of cereals the problem. I need not dwell on them now.

I would only like to assure the House that the Government of India does go by certain principles. Of course, we have to take certain pragmatic decisions because we have to consider the central stock position. But other issues are taken into consideration on the basis of certain principles. We make allotments on the basis of local production, on the basis of State production. The consumption patterns are also taken into consideration. The population is also taken into consideration. I would like to assure the hon. Member that we will continue to make efforts to help Bihar.

The position of Bihar is being complicated by the present political agitation. We should not try to exaggerate the problem. I have no doubt in my mind that there would not be starvation in Bihar. We shall be able to manage the food economy. The inflow into Bihar of food during the next four months would be much larger as compared to the last few months.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: What about railwaymen?

SHRI S M. BANERJEE: What about U.P.?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: This year U.P. had some difficulties. There was some setback to production and there were some difficulties. But the prospects of kharif crop in U.P., because of very good rainfall, are very good....

SHRI S. M. BANERJEE: I have raised specific question about biscuit-manufacturing companies. People have lost their jobs.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: We make the allotment to the State Governments and it is entirely left to the discretion of the State Governments how much they will allot to various classes of consumers. For no part of the country have we assumed responsibility for making allocation to particular categories of consumers. That is entirely the responsibility of the State Governments. They can ask for more quota from us. That is a different thing. The point is that it is their responsibility. We do not take the responsibility for *inter se* distribution as between the various categories of consumers.

As far as railway employees are concerned, the understanding was this. If the railwaymen's societies would like to purchase, we would help them in purchasing foodgrains from surplus States so that they are in a position to distribute through their cooperatives.

श्री कमल मिश्र मधुकर : अन्न के मामले मे आत्म निर्भर बनाने के लिये केरल टाइप पैटर्न पर भूमिसुधार कानून बहुत सी जगहों पर बन चुके हैं। बिहार मे भी यह कानून बन चुका है लेकिन अभी तक लागू नही हुआ है। मैं जानना चाहता हू कि इस कानून के लागू होने से उत्पादन बढ़ाने मे सहायता मिलेगी या नही ?

MR. CHAIRMAN: It is not strictly relevant to the question

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Implementation of land reforms is the responsibility of the State Governments

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

18 13 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 30 1974/Sravana 8, 1896 (Saka).

MGIPND—P M.R—1256 L.S—JC—2050—29-8-74—978.